

- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने कल प्रधानमंत्री रेहडी—पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि – पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पूरे देश के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है।
- द्वीपसमूह में 08 सितम्बर से 19 सितम्बर तक सर्किट बैठक का आयोजन किया जाएगा।
- राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025–26 के लिए एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट सह चयन ट्रायल का आयोजन 31 अगस्त को किया जाएगा।

<><><><><><><>

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने कल प्रधानमंत्री रेहडी—पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि – पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमण्डल ने 31 दिसंबर 2024 से आगे की अवधि के विस्तार का भी अनुमोदन किया। इसे अब 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया गया है। योजना का कुल परिव्यय सात हजार 332 करोड़ रुपये है। इस पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित एक दशमलव पन्द्रह करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना है, इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग पर संयुक्त रूप से रहेगी। पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त में बड़ी हुई ऋण राशि दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई लिंकड रूपए क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा और थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैंक प्रोत्साहन शामिल है। यूपीआई लिंकड रूपए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से स्ट्रीट वेंडरों को किसी भी आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट मंडल खुदरा और थोक लेनिन पर 1600 रुपए तक के कैशबैंक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।

<><><><><><>

प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। 28 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों की दुष्क्र से मुक्ति का उत्सव बताया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना है। यह योजना बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता—आधारित ऋण, धन प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी कई वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तथा बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करती है। किसी भी बैंक शाखा या बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट में शून्य शेष राशि पर खाता खोला जा सकता है। प्रत्येक बैंक खाता बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है।

<><><><><><>

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पूरे देश के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने का आव्वान किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस पहल से अवगत कराया है।

<><><><><><>

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंतर्गत ईआईएसीपी द्वीप जैव विविधता केंद्र की ओर से विश्व ओज़ोन दिवस के अवसर पर “विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक” विषय पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग में 13 सितम्बर को दिन में 11 बजे आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में इच्छुक शिक्षक, शोधार्थी, कॉलेज और स्कूली विद्यार्थी भाग ले सकते हैं।

<><><><><><>

द्वीपसमूह में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश, 2005 लागू कर दिया गया है। इसके तहत ई—केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो हर पाँच साल में किया जाना अनिवार्य है। पंजीकृत सभी राशन कार्ड धारकों को कहा गया है कि कोई भी सदस्य अठारह वर्ष की आयु से पहले अलग राशन कार्ड रखने के लिए पात्र नहीं होगा, पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार नम्बर दर्ज किया जाएगा और पाँच वर्ष की आयु पूरी होने के एक वर्ष के भीतर बच्चों के

लिए ई—केवाईसी अपडेट किया जाएगा। जिन लाभार्थियों ने प्रिले छह महीनों के दौरान राशन कार्ड का लाभ नहीं उठाया है, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। ऐसे निष्क्रिय राशन कार्डों को सक्रिय करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में 08 सितम्बर से 19 सितम्बर तक सर्किट बैठक का आयोजन किया जाएगा। कोलकाता पीठ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उप रजिस्ट्रार ने कहा है कि इस दौरान नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएँगे। जिन विभागों के मामले कैट के पास विचाराधीन हैं, उनसे संबंधित दस्तावेजों के साथ सरकारी वकील या पैनल अधिवक्ताओं से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। विभागाध्यक्षों से भी अपने नोडल अधिकारियों को सुनवाई के दिन संबंधित दस्तावेजों के साथ न्यायाधिकरण में उपस्थित रहने का निर्देश देने को कहा गया है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अगस्त सुबह 9 बजे जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के फुटबॉल मैदान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025–26 के लिए एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट सह चयन ट्रायल का भी आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><>

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर भाग लेने के लिए साइकिंग एसोसिएशन अंडमान निकोबार दक्षिण अंडमान जिला ट्रैक एवं रोड साइकिंग चैंपियनशिप—सह—चयन ट्रायल का आयोजन करेगा। इस संबंध में, साइकिंग एसोसिएशन ने साइकिल चालकों, संस्थाओं और क्लबों से तीस अगस्त तक नेताजी स्टेडियम स्थित राज्य ओलंपिक संघ कार्यालय में पंजीकरण कराने को कहा है। चयन ट्रायल 31 तारीख को सुबह 6 बजे आयोजित किया जाएगा।

<><><><><><>

प्रशासन के पर्यावरण और वन विभाग ने शहीद द्वीप के निवासियों से समुद्री रेत संग्रहण हेतु परमिट जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदक के पास वैध भूमि दस्तावेज़ का होना अनिवार्य है, जो सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। आवेदन शहीद द्वीप वन विभाग कार्यालय में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच जमा किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 सितंबर है।

<><><><><><><>

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से जुलाई 2025 सत्र के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम को छोड़कर सभी कार्यक्रमों में नए प्रवेश की तिथि और अगले वर्ष के लिए पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इच्छुक छात्र इग्नू की अधिकारिक वेबसाइट 'छात्र सेवा—प्रवेश अनुभाग' से नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><>

जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार आठ सितम्बर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। ग्यारह सितम्बर को अस्थाई वरीयता सूची जारी की जाएगी। दावे या आपत्तियां पंद्रह सितम्बर तक जमा किए जा सकते हैं। अंतिम वरीयता सूची सत्रह सितम्बर को जारी की जाएगी। अधिक जानकारी कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

<><><><><><>